



# CURRENT AFFAIRS

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

**DATE: 27-08-25** 







# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Wednesday, 27 Aug, 2025

# **Edition: International Table of Contents**

Page 01	भारत आज से 50% अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के लिए
Syllabus : GS 2 : International	तैयार है
Relations	
Page 06	सर्वेक्षण के अनुसार, कुल नामांकन में सरकारी स्कूलों
Syllabus: GS 2: Social Justice /	की हिस्सेदारी 55.9% है
Prelims	
Page 06	आदि कर्मयोगी पहल, आदिवासी 'परिवर्तन के नेताओं'
Syllabus : GS 2 : Governance and	को ग्राम स्तर पर आगे बढ़ाएगी
Social Justice	
Page 08	झूठी धार्मिकता: न्यायालयों को नागरिकों के अधिकारों
Syllabus : GS 2 : Indian Polity	की रक्षा करनी चाहिए, राज्य को अनियंत्रित शक्ति
	नहीं देनी चाहिए
Page 08	चुनाव आयोग की सुरक्षा घेरा संविधान और कानून है
Syllabus : GS 2 : Indian Polity	
Page 08 : Editorial Analysis	भारत की आर्थिक कमज़ोरियों का लैंगिक पहलू
Syllabus : GS 2 : Social Justice	





## Page 01: GS 2: International Relations

अमेरिका ने भारत से आने वाले आयातित उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया है, जिससे कुल शुल्क लगभग 50% तक पहुँच गया है। इसका सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों पर जो पहले से ही मूल्य प्रतिस्पर्धा में कमजोर हैं। अनुमान है कि अमेरिका को होने वाले 47–48 अरब डॉलर के निर्यात का 55% हिस्सा अब गंभीर मूल्य हानि का सामना करेगा। यह भारत की विदेशी व्यापार नीति, आर्थिक विकास दर और रणनीतिक संबंधों के लिए बड़ी चुनौती है।

# India braces for impact of 50% U.S. tariffs from today

No comment from Ministry of External Affairs on any govt. plans for counter-tariffs against the U.S.

India has been pushing the Swadeshi mantra and the PM has called on citizens to buy local

55% of U.S.-bound shipments, worth \$47-48 billion, are at a disadvantages of 30% to 35%

#### T.C.A. Sharad Raghavan Suhasini Haidar NEW DELHI

he United States government is getting ready to implement the 25% additional tariffs imposed on India by U.S. President Donald Trump, which come into effect on Wednesday. On Tuesday, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) uploaded a notification of the new tariffs to be published in the official register the following day.

The Indian government is pushing a Swadeshi mantra to reduce the economy's reliance on exports. with Prime Minister Narendra Modi on Tuesday calling upon Indians to be "vofor local" and buy Indian goods. Indian exporters, however, are bracing themselves for a sharp

fall in business to the U.S., with early estimates pred icting that more than \$47 billion worth of goods will face the 50% tariff rate This includes the 25% tariff that Indian imports have attracted since August 7 plus an additional 25% ta-riff imposed as a penalty for India's import of oil from Russia.

#### Exemptions given

This additional tariff will not apply to iron, steel, or aluminium products; passenger vehicles such as sedans, sport utility vehicles, crossover utility vehicles, minivans, cargo vans, and light trucks: semi-finished copper, and intensive copper derivative products, among others.

The Ministry of External Affairs did not comment on whether India is planning any counter-measures

or counter-tariffs against the United States, though a senior official said that India stands by the MEA's earlier statement calling

the sanctions "unfair, un

and

justified

, unreasonable The U.S. DHS notifica tion detailed the implementation of Mr. Trump's executive order.

"To effectuate the President's Executive Order

#### Tariff travails

ent is now pushing a Swadeshi mantra to reduce the economy? reliance on exports, Indian exporters are bracing themselves for a sharp fall in business with the



exports rende uncompetitive compared to neighbouring countries, warns FIEO Sectors to be hit: Apparel, textiles, geExtent of impact: Imports from these

sectors could plunge 70%

14329 of August 6, 2025... which imposed a specified rate of duty on imports of articles that are products of India, the Secretary of Homeland Security has determined that appropriate action is needed to modify the Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) as set out in the Annex to this notice,"

The duties set out in

the notice said.

the Annex to this document are effective with respect to products of India that are entered for consumption, or withdrawn from warehouse for consumption, on or after 12:01 a.m. eastern daylight time on August 27, 2025," it added.

The MEA did not comment on whether the additional tariffs will be on the agenda when Prime Minister Modi meets Chinese President Xi Jinping in Tianjin on August 30. Last week, the Chinese Ambassador to India had referred to the U.S. as a "bully", saying the Chinese government opposes the tariffs and "firmly stands with India" on the issue.

Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra, too, said the central bank would not be found wanting" in supporting those sectors that will be adversely affected by the tariffs.

The Goods and Services Tax (GST) Council is all set to meet on September 3 to 4 to decide on a slew of rate cuts and rationalisation measures suggested by the Union government to not only ease the overall tax rate borne by consumers, but also simplify the indirect tax regime.

This consumption boost

is expected to mitigate some of the slowdown in economic growth that higher tariffs could cause.

#### Worried exporters

Indian exporter bodies and trade experts, howev er, are projecting a sub-stantial hit to India's exports.

According to the Federa tion of Indian Export Or ganisations president S.C. Ralhan, the development could "severely impact" India's exports to the U.S., "with approximately 55% of India's U.S.-bound ship ments (worth \$47-48 billion) now exposed to pricing disadvantages of 30% to 35%, rendering them uncompetitive in comparison to competitors from China, Vietnam, Cambodia, Philippines, and other Southeast and South Asian countries".

#### मुख्य भाग

### 1. शुल्क का संदर्भ

- अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के अनुसार 27 अगस्त 2025 से नए टैरिफ लागू कर दिए।
- इस अतिरिक्त शुल्क से इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा और यात्री वाहन जैसे कुछ उत्पाद मुक्त रखे गए हैं।
- दंडात्मक रूप से यह निर्णय भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद के कारण भी जोड़ा जा रहा है।

#### 2. भारत पर प्रभाव

- व्यापारिक झटका: लगभग 55% निर्यात अब 30–35% महंगा हो जाएगा, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धा चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस जैसे देशों से कमजोर होगी।
- आर्थिक मंदी का खतरा: निर्यात में गिरावट से GDP विकास दर प्रभावित हो सकती है और चालू खाता घाटा बढ़ सकता

#### **DAILY CURRENT AFFAIRS**





- रोज़गार पर असर: कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों पर संकट आ सकता है।
- रणनीतिक दबाव: यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों को जिटल बना सकता है, खासकर रक्षा व प्रौद्योगिकी सहयोग में।

#### 3. भारत की नीति प्रतिक्रिया

- घरेलू मोर्चा: सरकार ने "वोकल फॉर लोकल" और स्वदेशी मंत्र पर ज़ोर दिया है।
- GST सुधार: GST परिषद (3-4 सितम्बर) दरों में कटौती और सरलीकरण पर विचार करेगी ताकि उपभोग बढ़े और निर्यातकों को राहत मिले।
- मौद्रिक समर्थन: RBI ने प्रभावित क्षेत्रों को सहारा देने का आश्वासन दिया है।
- कूटनीतिक संतुलन: विदेश मंत्रालय ने इसे "अनुचित और अव्यवहारिक" कहा है। चीन ने भी अमेरिका की आलोचना करते हुए भारत का समर्थन किया है।

#### 4. व्यापक निहितार्थ

- भूराजनीतिक संकेत: चीन द्वारा भारत का समर्थन एक संभावित नई साझेदारी की ओर संकेत करता है।
- वैश्विक व्यापार व्यवस्था: यह कदम बहुपक्षीय संस्थाओं (जैसे WTO) की कमजोर स्थिति और संरक्षणवाद के बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
- आत्मिनर्भर भारत: यह संकट भारत को नए बाजारों की खोज, घरेलू उद्योगों को मज़बूत करने और निर्यात विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।

#### निष्कर्ष

अमेरिका के इन ऊँचे टैरिफ़ों से भारतीय निर्यातकों को गहरा झटका लगेगा, विशेषकर श्रम-प्रधान उद्योगों को। हालाँकि GST सुधार, RBI समर्थन और "वोकल फॉर लोकल" जैसी पहलें कुछ राहत दे सकती हैं, परंतु यह घटना स्पष्ट करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक राजनीतिक निर्णयों पर अत्यधिक निर्भर है। दीर्घकाल में भारत को निर्यात गंतव्यों का विविधीकरण, बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना, और आत्मनिर्भर भारत ढाँचे को तेज़ी से लागू करना होगा तािक ऐसे बाहरी आर्थिक झटकों से बचाव हो सके।





#### **UPSC Prelims Practice Question**

# Ques: भारत पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है जिससे कुल शुल्क लगभग 50% हो गया है।
- 2. इस अतिरिक्त शुल्क से लोहे, इस्पात, एल्युमिनियम और यात्री वाहन मुक्त रखे गए हैं।
- 3. यह टैरिफ आंशिक रूप से भारत द्वारा रूस से तेल आयात करने से जुड़ा है।

# उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans: (d)

#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques: "वैश्विक व्यापार में बढ़ता संरक्षणवाद भारत की विकास रणनीति के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।" इस कथन की चर्चा हाल ही में भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ़ के संदर्भ में कीजिए। 250 Words)





## Page 06: GS 2: Social Justice / Prelims

राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण (NSS) के 80वें चरण में किए गए व्यापक मॉड्यूलर सर्वे (शिक्षा) से स्पष्ट हुआ है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब भी सरकारी विद्यालय मुख्य आधार बने हुए हैं। सर्वेक्षण ने नामांकन, घरों द्वारा शिक्षा पर व्यय, ग्रामीण–शहरी असमानता तथा निजी कोचिंग पर निर्भरता जैसे पहलुओं को उजागर किया है। यह निष्कर्ष शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनोतियों व संभावनाओं दोनों को सामने लाते हैं।

# Govt. schools account for 55.9% of total enrolments, says survey

66% of students are in public institutions in rural areas as against 30.1% in urban; private unaided schools account for 31.9% of enrolment; nearly a third of all students get private coaching, says study undertaken as part of National Sample Survey

#### Maitri Porecha

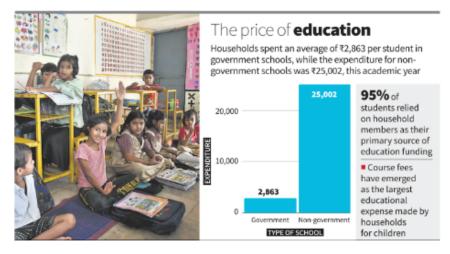
NEW DELHI

tudents enrolled in private or non-government schools across India end up paying nearly nine times more in school fees than those enrolled in government schools.

A third of all students across education Boards opt for private coaching in addition to classes in school, data collected by the Comprehensive Modular Survey (Education) for April-June 2025 as part of the 80th round of the National Sample Survey (NSS) revealed.

The average per-student expenditure made by households on school education during the current academic year (2025-26) in government schools is estimated at ₹2,863, while it was significantly higher at ₹25,002 in non-government schools.

Nearly a third of all students (27%) were taking or had taken private coaching during the current academic year. This trend was more common in urban areas (30.7%) than in rural



areas (25.5%).

The data focused specifically on household expenditure for currently enrolled students in school education. Data were collected from 52,085 households and 57,742 students across India through computer-assisted personal interviews.

The survey says government schools play a key role in providing education across India, accounting for 55.9% of total enrolments.

It is higher in rural areas, where two-thirds (66%) of students are enrolled as against 30.1% in urban areas. Private unaided (recognised) schools account for 31.9% of enrolment nationwide.

#### Education expenses

Among the students who paid for school education, 95% reported that the first major source of their funding was from other household members. This trend is consistent across both rural (95.3%) and urban (94.4%) areas.

On the other hand, 1.2% of the students reported that government scholarships were their first major source of funding for school education.

Course fees have emerged as the largest education expense made by households for children's education.

Across all types of schools at the all-India level, the highest average expenditure per student during the current academic year was on course fees − ₹7,111 − followed by textbooks and stationery − ₹2,002.

Rural-urban differences Urban households pay significantly more for education and related expenses across all categories.

Notably, the average expenditure on course fees in urban areas is estimated at ₹15,143, whereas it is ₹3,979 in rural areas.

"This trend of higher expenditure in urban areas is evident for other types of education-related expenses such as transportation, uniforms, and textbooks," the survey states.

Only 26.7% of students enrolled in government schools reported paying course fees, in contrast to 95.7% of students in nongovernment schools. Among different types of non-government schools, 98% students reported paying course fees in private unaided schools in urban areas. In rural areas, 25.3% of students reported paying course fees in government schools.

The primary objective of the survey was to generate national-level estimates of average expenditure on school education and private coaching during the current academic year, a press statement released by the Ministry of Statistics said.





#### मुख्य भाग

#### 1. नामांकन की स्थिति

- **सरकारी स्कूल**: कुल नामांकन का 55.9% हिस्सा।
- ग्रामीण-शहरी अंतर:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में 66% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में।
  - शहरी क्षेत्रों में केवल 30.1%।
- निजी स्कूल: निजी मान्यता प्राप्त (बिना सहायता वाले) विद्यालयों में 31.9% नामांकन।

#### 2. घरेलू व्यय

- सरकारी बनाम निजी:
  - सरकारी स्कूल प्रति विद्यार्थी खर्च: ₹2,863।
  - गैर-सरकारी स्कूल: ₹25,002 लगभग 9 गुना अधिक।
- मुख्य खर्च: पाठ्य शुल्क (₹7,111), किताबें व स्टेशनरी (₹2,002)।
- वित्त स्रोत:
  - 95% खर्च परिवार वहन करते हैं।
  - केवल 1.2% विद्यार्थी छात्रवृत्ति पर निर्भर।

## 3. निजी कोचिंग पर निर्भरता

- कुल विद्यार्थियों का लगभग 27% (हर तीन में से एक) निजी कोचिंग ले रहा है।
- शहरी क्षेत्रों में यह दर 30.7%, ग्रामीण में 25.5%।
- इससे विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का दबाव झलकता है।

## 4. ग्रामीण-शहरी असमानताएँ

- शहरी परिवार शिक्षा पर कहीं अधिक खर्च करते हैं:
  - पाठ्य शुल्क: शहरी ₹15,143, ग्रामीण ₹3,979।
  - परिवहन, यूनिफ़ॉर्म, किताबों में भी यही अंतर।
- यह शैक्षिक असमानता और पहुँच की समस्या को दर्शाता है।

#### 5. नीतिगत निहितार्थ

• सकारात्मक पक्ष: ग्रामीण भारत में शिक्षा उपलब्ध कराने में सरकारी स्कूलों की अहम भूमिका।





# • चुनौतियाँ:

- सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर प्रश्न,
- निजी स्कूलों की ऊँची फ़ीस,
- छात्रवृत्ति का सीमित दायरा।

#### • आगे की राह:

- सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे और शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार।
- गरीब व कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों का विस्तार।
- निजी कोचिंग पर नियंत्रण और विद्यालयों में समग्र शिक्षा पर जोर।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को लागू करना।

#### निष्कर्ष

एनएसएस डेटा दर्शाता है कि सरकारी विद्यालय अब भी भारत की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। किंतु निजी शिक्षा पर अधिक खर्च और कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता, शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता व समानता संबंधी चुनौतियों को उजागर करती है। इस अंतर को कम करने के लिए दोहरी रणनीति आवश्यक है—

- (1) सार्वजनिक शिक्षा में निवेश और गुणवत्ता सुधार, तथा
- (2) निजी शिक्षा व कोचिंग पर विनियमन।

इसी से भारत सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) "सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" को प्राप्त कर सकेगा।

#### **UPSC Prelims Practice Question**

Ques: NSS (2025) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग कितना है?

- (a) 30.1%
- (b) 25.5%
- (c) 66%
- (d) 55.9%

#### Ans: (c)

#### **UPSC MainsPractice Question**

Ques: सरकारी विद्यालय भारत की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, किंतु निजी शिक्षा व कोचिंग पर बढ़ता व्यय गहरी चुनौतियों की ओर संकेत करता है। हालिया NSSO आँकड़ों के संदर्भ में विवेचना कीजिए।





## Page: 06: GS 2: Governance and Social Justice

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धर्ति अबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आदि कर्मयोगी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य देशभर के जनजातीय अंचलों में 20 लाख "परिवर्तनकारी नेता" (Change Leaders) तैयार करना है, जो न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देंगे बल्कि सामुदायिक भागीदारी, आत्मिनर्भरता और स्थानीय दृष्टि को भी प्रोत्साहित करेंगे।

# Adi Karmayogi initiative to put tribal 'change leaders' through their paces at village level

Abhinay Lakshman NEW DELHI

Lighting candles, role-play, cognitive group tasks, and "knot-tying" and "fish-bowl" exercises – at the core of efforts to create a "cadre" of 20 lakh "change leaders" for tribal villages under the Adi Karmayogi initiative of the Tribal Affairs Ministry is a training

district, and block officials.

The programme will be extended to the village level in the coming months.

programme that conducts

such activities for State.

Government officials told *The Hindu* that the idea was to adopt a "participatory" approach to problem-solving.

This involves driving home messages such as "the solution comes from within", "not dwelling on problems", "initiating action", and "creating opportunity from challenges", according to the Ministry's



Ground work: The first phase involves holding training sessions down to the village level across 324 districts. X/@TRIBALAFFAIRSIN

concept note for the initiative, which is being run under the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyaan programme for last-mile scheme delivery.

The Adi Karmayogi initiative was conceived of earlier this year after a two-day national workshop, where, at a brainstorming session, it was concluded that the reason tribal areas continued to face backwardness was not a lack of schemes for them but a "lack of motivation"

in those implementing them.

#### 'Village vision'

The government, through the training activities mentioned above, intends to create 240 State-level master trainers, 2,750 district-level trainers, and over 15,000 block-level trainers, who will be responsible for taking the training down to 20 lakh village-level officials, volunteers, and community leaders.

Apart from this, the pro-

gramme intends to help residents to draw up their own "Village Vision" documents for 2030 for each of the one lakh target villages across over 550 districts, which are to be depicted as "public murals" and will become "aspirational blueprints" for the State machinery to follow.

Under the programme, the Ministry said it will also set up one lakh Adi Seva Kendras – meant to act as a single-point interface for villagers trying to access the gamut of welfare schemes meant for them so that 100% saturation can be achieved.

The first phase of the initiative involves holding these training sessions at the village level across 324 districts. Currently, regional training sessions are conducted where State-level master trainers are trained.

Most of the State-level sessions are also conduct-

ed for training district-level trainers, following which block-level and village-level training will take place, according to officials. Once the sessions reach the village level, each session will have 15 volunteers to participate in them.

#### Prescribed activities

At these training sessions, the "prescribed" activities include a "lighting the candle" exercise to encourage participants not to "curse darkness" but "bring the light".

A "fish bowl exercise" asks participants to imagine themselves as fish in a bowl and get to know each other.

The "village scenario role play" exercise involves imagining a village of animal rearers trying to solve water scarcity after the state machinery fails to act and the Deputy Commissioner's staff is rushed to find a solution.

# मुख्य भाग

# 1. पहल की पृष्ठभूमि

- अनेक सरकारी योजनाओं के बावजूद जनजातीय क्षेत्र अभी भी पिछड़े हैं।
- एक राष्ट्रीय कार्यशाला में यह निष्कर्ष निकला कि समस्या योजनाओं की कमी नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने वालों की प्रेरणा और भागीदारी की कमी है।
- इसलिए पहल का लक्ष्य है व्यवहारिक बदलाव और स्थानीय नेतृत्व का निर्माण।





#### 2. कार्यक्रम की संरचना

- प्रशिक्षण श्रृंखलाः
  - 240 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर → 2,750 जिला स्तरीय ट्रेनर → 15,000+ प्रखंड स्तरीय ट्रेनर → अंततः 20 लाख गाँव-स्तरीय स्वयंसेवक व नेता।
- सहभागी अभ्यास:
  - दीप प्रज्वलन (अंधकार को कोसने के बजाय प्रकाश फैलाने का संदेश),
  - फिश बाउल चर्चा,
  - भूमिका-निभाने के अभ्यास (गाँव की समस्या समाधान)।
- विलेज विज़न 2030: 1 लाख लिक्षित गाँवों में सामुदायिक दृष्टि दस्तावेज तैयार होंगे और दीवार चित्रों (public murals) के रूप में प्रदर्शित किए जाएँगे।
- आदि सेवा केंद्र: 1 लाख केंद्र स्थापित होंगे, जो सभी योजनाओं का सिंगल-विंडो एक्सेस पॉइंट बनेंगे।

#### 3. महत्व

- सशक्तिकरणः समाधान "भीतर से" आने की भावना विकसित होगी।
- क्षमता निर्माण: अधिकारियों व स्वयंसेवकों में प्रेरणा व कौशल का विकास।
- बेहतर क्रियान्वयन: अंतिम छोर तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित होगी।
- सामाजिक एकजुटताः साझा विज़न दस्तावेज़ सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देंगे।

# 4. संभावित चुनौतियाँ

- प्रशिक्षण के बाद प्रेरणा को स्थायी बनाए रखना।
- औपचारिकता का खतरा कहीं यह केवल प्रतीकात्मक अभ्यास न बनकर रह जाए।
- विलेज विज़न 2030 को राज्य की योजना व बजट प्रक्रिया में जोड़ना।
- केवल संख्या गिनने के बजाय जमीनी असर पर निगरानी।

#### निष्कर्ष

आदि कर्मयोगी पहल भारतीय शासन-प्रणाली में एक अभिनव प्रयोग है, जो योजनाएँ बनाने से अधिक उन लोगों और समुदायों को प्रेरित करने पर ध्यान देता है जो उन्हें लागू करते हैं। यदि यह पहल सही ढंग से लागू होती है तो यह जनजातीय विकास को एक सामुदायिक आंदोलन का रूप दे सकती है। किंतु इसकी सफलता निरंतर प्रशिक्षण, प्रशासनिक समन्वय और जमीनी प्रभाव की सटीक निगरानी पर निर्भर करेगी।

#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques : आदि कर्मयोगी पहल का उद्देश्य योजनाओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में सहभागी समस्या-समाधान और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना है। इसके महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 words)





### Page 08: GS 2: Indian Polity

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों पर की गई आपित्तजनक टिप्पणियों के मामले में केंद्र सरकार से कहा कि वह सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने हेतु दिशा-निर्देश बनाए। उद्देश्य भले ही गरिमा की रक्षा हो, किंतु यह कदम कार्यपालिका को और अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। संपादकीय चेतावनी देता है कि इस तरह के निर्देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क)) को संकुचित कर सकते हैं और लोकतंत्र में अतिरिक्त अपराधीकरण को जन्म दे सकते हैं।

#### मुख्य भाग

# 1. संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद 19(1)(क): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी।
- अनुच्छेद 19(2): यथोचित प्रतिबंध जैसे संप्रभुता, शांति-व्यवस्था, शांलीनता, नैतिकता इत्यादि।
- न्यायपालिका की भूमिका: स्वतंत्रता की रक्षा करना और प्रतिबंधों की सख्त व्याख्या करना, न कि कार्यपालिका को अतिरिक्त शक्तियाँ देना।

## 2. संपादकीय में उठाई गई चिंताएँ

- न्यायपालिका का कार्यपालिका को बढ़ावा: नए दिशा-निर्देशों का आग्रह करके
   न्यायपालिका, पहले से ही शक्तिशाली कार्यपालिका को और बल दे रही है।
- सेंसरशिप की फिसलन भरी ढलान: यदि अभद्र हास्य या आपत्तिजनक भाषण को अपराध घोषित किया जाए तो राजनीतिक आलोचना, पत्रकारिता, व्यंग्य और कला भी दब सकती है।
- चिलिंग इफ़ेक्ट: नागरिक आत्म-सेंसरशिप अपनाएँगे, फ़िल्मकार सामाजिक विषयों से दूर होंगे और पत्रकार FIR का सामना करेंगे।
- मौजूदा सुरक्षा उपाय पर्याप्तः घृणास्पद भाषण और हिंसा के लिए उकसाने वाले भाषण पहले से ही IPC व IT अधिनियम के तहत दंडनीय हैं।

# 3. ऑनलाइन विनियमन का परिप्रेक्ष्य

- । ा नियम, 2021 और उनके संशोधन पहले ही सरकार को सामग्री हटाने का अधिकार देते हैं।
- इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।
- अतिरिक्त शक्तियाँ भारत को राज्य-नियंत्रित डिजिटल स्पेस में बदल सकती हैं।

# **False righteousness**

Courts must protect rights of citizens, not allow the state untrammelled power

n urging the Union government to work on guidelines to regulate speech on social media, the Supreme Court of India is seeking to empower an executive that is already weaponising the legal limits on freedom of expression. In response to a petition by a non-profit assailing derogatory remarks by online figures against disabled persons, the Court issued instructions that further a problematic trend of the judiciary egging on the state to encroach on legal grey areas with statutory restrictions that undermine constitutionally guaranteed rights. To regard distasteful humour, however disturbing it might be, as a problem to be solved through the courts and by executive rulemaking, is to fall into a deceptive trap of imagined righteousness that progressive democracies should avoid. There are always unpleasant consequences in expanding powers to police speech: partisans wield their powers to ferociously monitor what is or is not appropriate, instrumentalising agencies of the state to suppress art and political speech they do not like; citizens find themselves constantly looking over their shoulder before expressing themselves. Under the overbearing atmosphere of censored expression, truths and ideas that must be reckoned with for a functioning democracy are stifled. People should not have to constantly look against asterisks that set terms and conditions for fundamental liberties. Film producers and directors have been pushed away from exploring subject matters that would help India progress socially, and journalists have been dealing with first information reports for carrying out their professional duties.

In recent years, the Union government has, formally and informally, expanded its control of online speech, with the problematic Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, and an amendment to those Rules that would allow social media companies to be proceeded against for content posted by users that has been flagged by the government. Monday's instructions seem set to expand those ambitions, which are themselves under challenge with the Supreme Court. Hate speech and speech inciting violence against minorities are criminalised in India, giving disadvantaged groups powerful avenues of recourse when they are legitimately wronged. Handing an executive, which already has a record of mala fide weaponisation of media and speech regulations, more powers would be dangerous in the extreme. At a fundamental level, such judicial pronouncements, which cite "misuse of freedom of speech" as a ground, seem to misperceive the framework of their institutional role: that of a protector of rights under a clear constitutional framework, and not of an unchallenged lord in a feudal society.

#### **DAILY CURRENT AFFAIRS**





#### 4. लोकतांत्रिक निहितार्थ

- स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र की रीढ़ है; असुविधाजनक सच्चाइयों को दबाना जवाबदेही को कमज़ोर करता है।
- न्यायपालिका की भूमिका: कार्यपालिका के अतिक्रमण पर अंकुश लगाना, न कि उसका विस्तार करना।
- "स्वतंत्रता के दुरुपयोग" पर अत्यधिक ध्यान एक जमींदारी मानसिकता को दर्शाता है, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से असंगत है।

#### निष्कर्ष

सोशल मीडिया अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश बनाने की न्यायालय की सलाह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो मौलिक स्वतंत्रताओं को क्षीण कर सकती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है, न कि उसकी शक्तियों को बढ़ाना। आपत्तिजनक भाषण की सामाजिक निंदा और मौजूदा क़ानूनों के अंतर्गत दंड संभव है, परंतु नए सेंसरशिप औज़ार देना लोकतंत्र, कला और मीडिया स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। भारत के संवैधानिक ढाँचे के लिए आवश्यक है कि अप्रिय होने पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए।

#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques: डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंतर प्रतिबंधों का सामना कर रही है। स्वतंत्रता और ऑनलाइन अभिव्यक्ति के नियमन के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 150 Words)





### Page 08: GS 2: Indian Polity

हालिया बेंगलुरु में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विवाद ने चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक और संवैधानिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है — जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। लेकिन हालिया घटनाक्रम और आयोग की प्रतिक्रिया ने उसकी शक्तियों की सीमाओं और संवैधानिक दायित्वों पर सवाल उठाए हैं।

# The ECI's ring fence is the Constitution and the law

wo major press conferences held in recent weeks have attracted a good deal of national attention. The first was held by the Leader of the Opposition (LoP) in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on August 7, 2025, in New Delhi, where he highlighted specific instances of manipulation of the voter list in the Mahadevapura Assembly segment of the Bangalore central parliamentary constituency during the 2024 general election. His disclosures included the fact that a large number of voters were enrolled in the voters list having the same address. In some cases, the 'father's name' was given as 'xyz' and the house number as '0'. According to Mr. Gandhi, these facts were unearthed by his team after painstaking research of the Election Commission of India (ECI) documents over six months. These disclosures by Mr. Gandhi have created consternation among the citizens of India - if these are true, the entire electoral system in India would lose its credibility and India's democracy will cease to be a genuine

#### The ECI's stand is unusual

The second press conference, also in New Delhi, was held by the Chief Election Commissioner (CEC) and his colleagues on August 17. It was expected that the CEC would clarify the issues raised by the LoP. However, the statements made by the CEC were a kind of a pushback against what the LoP had said in his press conference. As a matter of fact, the press conference by the CEC left citizens none the wiser as many basic questions were just ignored. The press conference ended with the CEC issuing an ultimatum to the LoP - to either submit the details of his disclosures with a sworn affidavit or apologise to the nation. This unusual stand of the ECI shows that it too has joined the political slugfest. This is a stand that will continue to rattle political parties for a long time.

The ECI is a high constitutional body that is entrusted with the task of superintending, directing and controlling the preparation of electoral rolls and conducting elections to Parliament, State legislatures and to the offices of the President and the Vice President of India. Article 324 of the Constitution vests enormous powers in the ECI to perform this task. It is mandated to conduct elections in a free and fair manner, which is a part of the basic structure of the Constitution. The Supreme Court of India has held that Article 324 is a reservoir of powers which the ECI can draw from in order to ensure that the elections are free and fair. However, it has to function within the Constitution and law.

Issuing an ultimatum to the LoP is not a part of



P.D.T. Achary is former Secretary General Lok Sabha

The Election

India has a

constitutional

obligation to

carefully

examine a

disclosure

serious

highlighting

complaint or a

irregularities in

electoral rolls

Commission of

the exercise of power under Article 324 or the election statutes. It is also not a part of the exercise of the powers of the ECI to join the adversarial political discourse in India.

The episode in Bangalore clearly points to the possibility of electoral lists being tampered with at some level. It is true that Mr. Gandhi's disclosures months after the general election do not fit into the procedural mould created by the Representation of The People Act, 1950. This Act and the rules made thereunder contain a just, fair and transparent procedural framework which provides for multiple layers of scrutiny and public inspection and a just procedure for resolution of disputes. Further, the election statutes assume that there is a finality about elections. Therefore, these statutes cannot deal with the issues which Mr. Gandhi has raised.

The question is how to deal with it. Attempts to counter it with senseless technicalities and a demand for sworn affidavits are non-productive. Article 324 confers enormous powers on the ECI so that it would prepare the rolls and conduct elections in a fair manner. Article 324 implies responsibilities and obligations to exercise that power judiciously. So, when a citizen makes a complaint or a disclosure highlighting serious irregularities in the preparation of the electoral rolls, it is the constitutional obligation of the ECI to examine this carefully and fix the faults in the system. How could 80 voters be registered under the same address when it is clear that they cannot be ordinarily resident there? They voted because their names were on the roll. Who enrolled them and under whose directions are serious questions which need an answer. A person can be registered in a voters' list only if he is ordinarily resident there. This term has been defined as permanent stay at a place. Are all these 80 people residing at one address permanently?

The Representation of The People Act 1950 provides for the revision of the electoral rolls. These rolls can be revised before every election or every year on the direction of the ECI or a special revision in a few constituencies or part thereof for which the ECI needs to record the reasons (Section 21 of The Representation of The People Act, 1950). Rule 25 of the Registration of Electors Rules, 1960 shows that the revision done annually can either be summary revision or intensive revision (intensively or summarily or partly intensively and partly summarily).

#### The Bihar SIR

The ECI is presently engaged in a special intensive revision (SIR) of electoral rolls in Bihar, a State where Assembly elections are due later this year. Actually, neither the Act not the Rules

contain any term such as special intensive revision.

There are separate provisions for intensive revision and special revision. This writer is of the view that the SIR suffers from certain legal infirmities. Intensive revision can be done only in January which is the qualifying date whereas a special revision can be done at any time; but this will be limited to certain constituencies or parts thereof.

The Bihar SIR has the qualifying date as July 1, which is in violation of Section 14(b) in The Representation of The People Act, 1950, which says that the 1st day of January shall be the qualifying date. Qualifying date is the date on which the revision or preparation of the roll begins.

There are a number of media reports on the chaotic conditions in Bihar as a result of the SIR. Intensive revision within a month is a contradiction in terms. Rule 25(2) of the Registration of Electors Rules, 1960, says that intensive revision means rolls have to be prepared afresh and Rule 8 says that the registration officer shall have to visit every dwelling house in the constituency to prepare the roll. It is anybody's guess whether the registration officers would be able to visit every dwelling house in the whole State within one month and complete the enumeration formalities in accordance with the procedure. This has sparked off a huge political agitation in the State.

The ECI claims that the enumeration process has been completed and 65 lakh voters have been deleted from the roll. Much against the wishes of the ECI, the Supreme Court, in an interim order, directed the ECI to publish the names and the reasons for their deletion. This order of the Court has been welcomed by all.

#### Prescient words

The ECI is a powerful constitutional authority. But the ECI does not have unfettered powers. The Constitution has not given anybody or any authority it created untrammelled powers which may be misused to the detriment of democracy.

In A.C. Jose vs Sivan Pillai and Ors. (1984), Justice S. Murtaza Fazal Ali said, "If the Commission is armed with such unlimited and arbitrary powers and if it ever happens that the persons manning the commission shares or is wedded to a particular ideology, he could by giving odd directions cause a political havoc or bring about a constitutional crisis, setting at naught the integrity and independence of electoral process, so important and indispensable to the democratic system." These are prophetic words.





#### 1. संदर्भ: हालिया घटनाएँ

- राहुल गांधी का खुलासा (7 अगस्त 2025): बेंगलुरु की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप (एक ही पते पर कई मतदाता, काल्पनिक विवरण आदि)।
- चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस (17 अगस्त 2025): चिंताओं का समाधान करने के बजाय, आयोग ने विपक्ष के नेता से शपथपत्र माँगने की अल्टीमेटम शैली अपनाई जिससे राजनीतिकरण की झलक मिली।
- बिहार SIR विवाद:
  - चुनाव आयोग ने 1 जुलाई को कालीफाइंग डेट मानकर विशेष पुनरीक्षण किया, जबकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1950 की धारा 14(ख) के अनुसार 1 जनवरी को ही कालीफाइंग डेट होना चाहिए।
  - इसके परिणामस्वरूप ६५ लाख मतदाता हटाए गए।
  - सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारण प्रकाशित करने का आदेश दिया जिसे पारदर्शिता की दिशा में कदम माना गया।

#### 2. विधिक और संवैधानिक ढाँचा

- अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग को चुनावों का "निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण" करने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु शक्तियों का भंडार बताया है।
- लेकिन ये असीमित नहीं हैं: आयोग को संविधान और विधि की सीमा में रहकर ही कार्य करना है, अतिरिक्त-कानूनी अधिकार नहीं ले सकता।
- RPA 1950 और नियम 1960: मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन और सुधार के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तय करते हैं पारदर्शिता और अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए।
- A.C. Jose बनाम शिवन पिल्लई (1984): सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि मनमाने अधिकार राजनीतिक अराजकता पैदा कर सकते हैं।

# 3. उजागर मुद्दे

- विश्वसनीयता पर सवाल: यदि हेराफेरी के आरोपों की जाँच न हुई तो लोकतंत्र पर से जनता का भरोसा घटेगा।
- प्रक्रियागत खामियाँ: बिहार की SIR प्रक्रिया विधि के अनुरूप नहीं थी एक माह में "गहन पुनरीक्षण" करना न तो व्यावहारिक है और न ही वैध।
- पक्षपात का भय: विपक्ष के नेता के साथ सीधे टकराव की स्थिति आयोग को राजनीतिक रूप से पक्षधर दिखा सकती है।
- पारदर्शिता का अभाव: लाखों नाम हटाने के पीछे पर्याप्त कारण या प्रक्रिया न बताना मतदाता विश्वास को कमजोर करता है।

#### **DAILY CURRENT AFFAIRS**





#### 4. आगे की राह

- पारदर्शिता बढ़ानाः नाम जोड़ने/हटाने के कारण सार्वजिनक करनाः राजनीतिक दलों और नागरिकों के लिए प्रक्रिया खोलना।
- विधिक अनुपालन: आयोग को RPA प्रावधानों और नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" जैसी अतिरिक्त-कानूनी व्यवस्था नहीं।
- न्यायिक निगरानी: बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप दर्शाता है कि संवैधानिक निकायों के अतिक्रमण पर न्यायपालिका अंतिम नियंत्रण रखती है।
- स्वतंत्रता सुदृढ़ करना: अnoop Baranwal मामला (2023) में सुझाए गए नियुक्ति सुधारों को पूरी तरह लागू करना आवश्यक है ताकि राजनीतिक प्रभाव से आयोग को मुक्त रखा जा सके।
- संस्थागत संयम: आयोग को राजनीतिक बयानबाज़ी से बचना चाहिए और निष्पक्ष संवैधानिक अंपायर के रूप में विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए।

#### निष्कर्ष

चुनाव आयोग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय लोकतंत्र की पवित्रता सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन उसकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं; वे संविधान और क़ानून की सीमा में बंधी हैं। बेंगलुरु और बिहार की घटनाएँ दर्शाती हैं कि आयोग को पारदर्शिता, वैधानिकता और निष्पक्षता से कार्य करना होगा। जैसा कि जस्टिस फ़ज़ल अली ने 1984 में चेताया था — असीमित शक्तियाँ लोकतंत्र को अस्थिर कर सकती हैं। नागरिकों का विश्वास बनाए रखना तभी संभव है जब चुनाव आयोग निष्पक्ष, कानूनसम्मत और पारदर्शी संरक्षक की भूमिका निभाए।

#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ देता है, लेकिन ये शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। हालिया मतदाता सूची विवादों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 words)





# **Page: 08 Editorial Analysis**

# The gender angle to India's economic vulnerabilities

ndia's economic ascent, which is now valued at \$4.19 trillion, has earned it a firm place in the global growth story. The country is poised to become the world's third-largest economy. Yet, this momentum now faces a formidable disruption – the proposed 50% tariffs by the United States President Donald Trump on Indian exports. Targeting \$40 billion in trade, these tariffs could shave off nearly 1% from India's GDP striking labour-intensive sectors such as textiles, gems, and leather and footwear which are critical industries that disproportionately employ women.

Unlike China, which has weathered U.S. tariffs through its manufacturing scale and diversified exports, India remains vulnerable. The U.S. accounts for 18% of India's exports; an increase in tariff could lead to 30%-35% cost disadvantage against competitors such as Vietnam leaving Indian exporters exposed. In this moment of crisis, these words appear prescient: "The strength of a nation lies in the strength of its women." India's failure to economically empower half its population is not just a social concern. It is now a strategic liability.

The tariffs threaten to destabilise employment for millions of Indian women. The textiles, gems, leather and footwear sectors, which employ nearly 50 million people, face a projected export decline of up to 50%. Additionally, India's existing low female labour force participation rate (FLFPR) has remained stuck between 37% and 41.7% far below the global average and China's 60%. According to the International Monetary Fund, closing the gender gap could boost India's GDP by 27% in the long term Yet, this is a promise that is stifled by cultural constraints, policy inertia and systemic barriers to employment.

#### The ticking clock

India is inching closer to its peak of its demographic dividend – a period where the working-age population vastly outnumbers dependents. This window, which could close by 2045, once fuelled growth in China, Japan, and the U.S. – economies now past their prime



Anurodh Lalit Iain

is Vice-Chairman, All India Congress Committee (Minority Department) and a Social Economic Analyst

The imposition of U.S. tariffs that threatens to impact millions of Indian women in labour-intensive sectors is a wake-up call — women need empowerment as economic agents

demographic advantage, with flattening growth curves. India must act to convert this fleeting dividend into sustained prosperity, and this means fully integrating women into the workforce.

Labour participation by rural women has inched up, but mostly in unpaid and low-productivity family work. In urban India, female workforce participation has stagnated. Safety concerns, unreliable public transport, lack of sanitation, and the crushing burden of unpaid care work continue to push women out of schools and jobs.

India risks the fate of Southern European economies such as Italy and Greece, where low FLFPR has placed a long-term drag on growth. The urgency is clear as it is a now-or-never moment.

#### Lessons from abroad, solutions at home

Global superpowers offer a road map. The U.S. leveraged women's labour during the Second World War with equal pay and childcare. China's post-1978 reforms drove 60% FLFPR through state-backed care and education. Japan raised its FLFPR from 63% to 70%, boosting GDP per capita by 4%. The Netherlands' part-time work model, with equal benefits, suits India, where women prefer such roles. These nations invested in legal protections, care infrastructure, and skills training, which are areas where India lags. Instead of short-term populism or blanket cash transfers, India needs structural reforms that empower women as economic agents.

Karnataka's Shakti scheme, which offers free public bus travel to women, is one such intervention. Since its launch in 2023, female ridership has surged by over 40%. The scheme has enhanced women's mobility for work, education, and enterprise – especially in rural and peri-urban areas. This has enabled more women to gain improved access to job markets, decrease their dependence on male family members, and achieve greater autonomy.

Redirecting spending from broad welfare schemes to targeted programmes such as tax

incentives for female entrepreneurs, digital inclusion drives, and gender-focused skilling platforms can yield more sustainable gains. Formalising gig and part-time work through updated labour codes and social protections would bring millions of women into the formal economy.

Urban Company, a leading gig platform, has onboarded over 15,000 women service providers. These workers earn ₹18,000-₹25,000 in a month, along with access to accident insurance, maternity benefits, and skill development. The platform's emphasis on safety, training and transparent pay highlights how gig work can be empowering particularly for semi-skilled urban women.

On the public side, Rajasthan's Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme has created over four crore person-days of work, with nearly 65% of jobs going to women. Its flexible, neighbourhood-based jobs in sanitation, greening and care work have enabled many first-time workers – especially those restricted by domestic duties – to enter the workforce. These cases show that when the state recognises and supports non-traditional work, it can unlock massive economic value.

#### A moment of reckoning

The looming U.S. tariff shock should serve as a wake-up call. India's economic vulnerabilities are not just due to external threats. They also stem from internal neglect, especially in tapping the potential of working-age women.

Empowering women is not a social gesture. It is a growth imperative. It is the linchpin of demographic dividend utilisation, export competitiveness and equitable development. If India seeks to become a true global powerhouse, its progress must be built on the shoulders of both its men and women. India stands at a crossroads. It can rise by investing in its women. Or it can falter by ignoring them. One path leads to resilience and inclusive growth. The other path leads to missed opportunities and economic

GS. Paper 02 Social Justice

UPSC Mains Practice Question: "महिला आर्थिक भागीदारी केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिए। (150 words)





#### **Context:**

भारत आज 4.19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है और निकट भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव इस विकास यात्रा में गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव श्रम-प्रधान क्षेत्रों — वस्त्न, रत्न, चमड़ा और जूता उद्योग — पर पड़ेगा, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएँ कार्यरत हैं। इस संदर्भ में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की कमी भारत की आर्थिक असुरक्षा को और गहरा कर देती है।

# मुख्य बिंदु

# 1. बाहरी चुनौतियाँ और लैंगिक आयाम

- अमेरिका भारत के 18% निर्यात का गंतव्य है। यदि टैरिफ लागू हुआ तो भारत के निर्यातकों को वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले 30%-35% लागत का नुकसान झेलना पड़ेगा।
- वस्त्र, रत्न, चमड़ा व जूता उद्योग जैसे क्षेत्रों में 50 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय है। इन पर असर सीधा महिला रोजगार पर पड़ेगा।

# 2. आंतरिक चुनौतियाँ

- भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) 37% से 41.7% के बीच है, जो वैश्विक औसत और चीन (60%) से काफी कम है।
- IMF के अनुसार, यदि भारत लैंगिक अंतर को पाटे तो दीर्घकाल में GDP में 27% की वृद्धि हो सकती है।
- परंतु सुरक्षा चिंताएँ, परिवहन व स्वच्छता की कमी और बिना वेतन वाले घरेलू कार्य महिलाओं को शिक्षा और नौकरी से बाहर कर देते हैं।

# 3. जनसांख्यिकीय लाभांश और समय की चुनौती

- भारत २०४५ तक अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के शिखर पर होगा।
- यदि महिलाओं को श्रम शक्ति में व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया, तो यह अवसर यूरोप के उन देशों (जैसे इटली, ग्रीस) की तरह चूक सकता है, जहाँ कम FLFPR ने दीर्घकालिक विकास को बाधित किया।





# 4. अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

- अमेरिका (द्वितीय विश्व युद्ध), चीन (1978 सुधार), जापान और नीदरलैंड्स ने महिला श्रम शक्ति बढ़ाने हेतु नीतिगत सुधारों से GDP में वृद्धि की।
- भारत को भी समान सुरक्षा, देखभाल अवसंरचना और कौशल प्रशिक्षण जैसे कदमों पर ध्यान देना होगा।

#### 5. भारत के हालिया प्रयास

- कर्नाटक की शक्ति योजना: महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता तक पहुँच आसान हुई।
- राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना: 65% रोजगार मिहलाओं को मिला, खासकर उन मिहलाओं को जो पहली बार श्रम बाजार में आईं।
- अर्बन कंपनी का गिग मॉडल: महिलाओं को सुरक्षित, प्रशिक्षित और औपचारिक आय के अवसर उपलब्ध करा रहा है।

#### निष्कर्ष

भारत के सामने दोहरी चुनौती है — एक ओर बाहरी दबाव (जैसे अमेरिकी टैरिफ) और दूसरी ओर आंतरिक उपेक्षा (महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी)। यदि भारत अपनी महिलाओं को आर्थिक शक्ति में बदलने में असफल रहता है तो यह विकास को दीर्घकालिक रूप से कमजोर कर देगा।

- महिलाओं का सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि आर्थिक आवश्यकता है।
- यह डेमोग्राफिक डिविडेंड के पूर्ण उपयोग, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने और समान व समावेशी विकास की कुंजी है।

भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है — या तो महिलाओं में निवेश कर वैश्विक महाशक्ति बने, या अवसर चूक कर आर्थिक नाजुकता की ओर बढ़े।